UnivColl International Multidisciplinary Research Journal

Volume 2 | Issue 4, April 2026, pp 1-8

ISSN (Online): 3108-1460

Homepage: https://univcolljournal.com

Title: भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा एवं विकास की संभावनाएँ: एक भौगोलिक अध्ययन

Author(s): डॉ. रितुम्भरा मल्ल

Affiliation(s): सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर

DOI: https://doi.org/10.65919/uimrj.2025.v2i4001

History: Received: 02 February 2026, Accepted: 10 March 2026, Published: 30 April 2026

Citation: मल्ल, ड. र. (2026). भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा एवं विकास की संभावनाएँ: एक भौगोलिक अध्ययन. *UnivColl International Multidisciplinary Research Journal, 2*(4). 1-6 https://doi.org/10.65919/uimrj.2025.v2i4001

Copyright: © 2026 The Author(s)

Licensing: Open access under CC BY-NC 4.0

Conflict of Interest: The author(s) declare no conflict of interest.

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Corresponding Author: डॉ. रितुम्भरा मल्ल

Published By: UnivColl Publications

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा एवं विकास की संभावनाएँ: एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. रितुम्भरा मल्ल

सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर

सारांश

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्र है। यह क्षेत्र हिमालय की दक्षिणी तलहटी तथा गंगा के मैदान के मध्य स्थित होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, जल संसाधनों और जैव विविधता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासीय स्थिति तथा विकास की संभावनाओं का भौगोलिक विश्लेषण करना है। अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतः सरयूपार क्षेत्र में स्थित भारत-नेपाल तराई के उन भागों पर केंद्रित है, जिनमें उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज तथा कुशीनगर जनपद सम्मिलित हैं। मूल अध्ययन में इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 9,775.59 वर्ग किलोमीटर तथा 2011 की कुल जनसंख्या 1,55,63,341 बताई गई है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग प्रस्तावित है। प्राथमिक आँकड़े सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार तथा द्वितीयक आँकड़े जनगणना, सरकारी विभागों एवं प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा, भूमि, रोजगार, स्वास्थ्य, ऋणग्रस्तता, परिवहन एवं संचार जैसी समस्याएँ जनजातीय विकास को प्रभावित करती हैं। साथ ही शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कृषि सुधार, लघु उद्योग, बाजार व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से विकास की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं।

प्रमुख शब्द: भारत-नेपाल तराई, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक-आर्थिक दशा, आजीविका, जनजातीय विकास, शिक्षा, रोजगार।

प्रस्तावना

मानव किसी भी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। किसी क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधन की गुणवत्ता, क्षमता और उत्पादकता पर भी निर्भर करता है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र में मानव की भागीदारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है। तराई क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदायों का जीवन भी प्राकृतिक पर्यावरण एवं उपलब्ध संसाधनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है।

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप इसे अन्य क्षेत्रों से अलग पहचान प्रदान करता है। यह क्षेत्र हिमालय की दक्षिणी तलहटी और मैदानी भागों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। क्षेत्र में नदियों, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, वन एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता ने मानव बसावट और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। अध्ययन सामग्री के अनुसार सरयू एवं नेपाल तराई के मध्य विस्तृत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कई जिले सम्मिलित हैं तथा क्षेत्र की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है।

तराई क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय समुदायों का ऐतिहासिक निवास रहा है। इन समुदायों की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराएँ, आर्थिक गतिविधियाँ तथा पर्यावरण के साथ संबंध विशिष्ट रहे हैं। पारंपरिक रूप से कृषि, पशुपालन, वन-आधारित गतिविधियाँ तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग इनकी आजीविका के प्रमुख आधार रहे हैं।

आधुनिक समय में शिक्षा, सड़क, बाजार, संचार, सरकारी योजनाओं और रोजगार के नए अवसरों के विस्तार ने इन समुदायों के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी है। फिर भी सामाजिक-आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हुआ है। भूमि की सीमित उपलब्धता, अशिक्षा, सीमित रोजगार अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गरीबी तथा बाजार तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ आज भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।

इसी संदर्भ में भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा तथा विकास की संभावनाओं का भौगोलिक अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र हिमालय की दक्षिणी तलहटी से लगे मैदानी भागों का महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ स्थलाकृति सामान्यतः समतल अथवा हल्की ढाल वाली है। घाघरा, राप्ती, गंडक तथा उनकी सहायक नदियाँ क्षेत्र के जल-प्रवाह और कृषि व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता के कारण कृषि इस क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में शामिल है।

क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों ने मानव बसावट को भी प्रभावित किया है। ऐतिहासिक रूप से अधिक आर्द्रता, दलदली भूमि और घने वन के कारण तराई का कुछ भाग प्रारंभिक स्थायी बसावट के लिए कठिन माना जाता था। समय के साथ दक्षिणी क्षेत्रों से मानव बसावट तराई की ओर बढ़ी तथा कृषि एवं आवासीय क्षेत्र का विस्तार हुआ।

तराई क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भारत और नेपाल के बीच सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क को भी प्रभावित करती है। सीमा से लगे क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ, बाजार, रोजगार, आवागमन और सांस्कृतिक संपर्क एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। इस कारण यहाँ जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि सीमा क्षेत्र की व्यापक भौगोलिक पृष्ठभूमि में करना आवश्यक है।

शोध पद्धति

प्रस्तावित अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अनुभवजन्य प्रकृति का होगा। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।

प्राथमिक आँकड़े चयनित जनजातीय परिवारों से संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। द्वितीयक आँकड़ों के लिए जनगणना, जनजातीय कल्याण संबंधी सरकारी प्रकाशन, जिला सांख्यिकी, आर्थिक सर्वेक्षण, संबंधित विभागों की रिपोर्ट तथा प्रकाशित शोध साहित्य का उपयोग किया जाएगा। उपलब्ध अध्ययन सामग्री में भी प्राथमिक आँकड़ों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण तथा द्वितीयक आँकड़ों के लिए सरकारी विभागों एवं जनगणना संबंधी स्रोतों के उपयोग की पद्धति प्रस्तुत की गई है।

आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत, वृद्धि दर, अनुपात, तुलनात्मक विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार सहसंबंध एवं अन्य सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्र, सारणी, आरेख एवं रेखाचित्रों का प्रयोग किया जाएगा।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

1. भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2. जनजातीय समुदायों की जनसांख्यिकीय संरचना, आजीविका, रोजगार, शिक्षा एवं जीवन-स्तर का भौगोलिक विश्लेषण करना।

3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों, सरकारी योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं की भूमिका का अध्ययन करना।

4. जनजातीय समुदायों के सामने उपस्थित प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की पहचान करना।

5. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आजीविका के विस्तार की संभावनाओं का विश्लेषण कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक स्थिति

अनुसूचित जनजातियाँ भारत की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके जीवन में विशिष्ट सामाजिक संगठन, भाषा, संस्कृति, परंपराएँ, रीति-रिवाज और सामुदायिक संबंध पाए जाते हैं। अध्ययन सामग्री में जनजातीय समाज को सामान्यतः एक ऐसे सामाजिक समूह के रूप में देखा गया है जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति, सामाजिक संगठन और विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान होती है।

तराई क्षेत्र के जनजातीय समुदायों की सामाजिक संरचना पर प्राकृतिक पर्यावरण तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रभाव रहा है। समुदायों का भूमि, जंगल, जल तथा पशुधन जैसे संसाधनों से पारंपरिक संबंध रहा है। सामुदायिक जीवन में परंपराओं, त्योहारों, खान-पान, पहनावे और सामाजिक संस्कारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

आधुनिक शिक्षा एवं संचार के विस्तार के कारण पारंपरिक सामाजिक संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। युवा पीढ़ी में आधुनिक शिक्षा, रोजगार और नगरीय जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ने से पारंपरिक व्यवसायों में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी ओर, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता भी बनी हुई है।

इस प्रकार जनजातीय समाज में परिवर्तन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, विवाह, परिवार, महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक भागीदारी तथा सांस्कृतिक पहचान भी सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

आर्थिक स्थिति एवं आजीविका

तराई क्षेत्र में जनजातीय समुदायों की अर्थव्यवस्था लंबे समय से प्राकृतिक संसाधनों और कृषि पर आधारित रही है। कृषि, कृषि मजदूरी, पशुपालन, वन उत्पादों का संग्रहण तथा स्थानीय श्रम इनके प्रमुख आजीविका साधनों में शामिल रहे हैं। अध्ययन सामग्री में यह उल्लेख मिलता है कि अनेक कमजोर सामाजिक समूहों की आर्थिक स्थिति भूमि की उपलब्धता तथा कृषि पर निर्भरता से प्रभावित होती है।

भूमि स्वामित्व का स्वरूप आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण निर्धारक है। जिन परिवारों के पास पर्याप्त कृषि भूमि है, उनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर हो सकती है, जबकि भूमिहीन या सीमांत परिवार कृषि मजदूरी तथा अन्य असंगठित कार्यों पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। सीमित भूमि, सिंचाई की कमी तथा पारंपरिक कृषि तकनीक के कारण कृषि से पर्याप्त आय प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

प्राकृतिक आपदाएँ भी आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तराई क्षेत्र में बाढ़, जलभराव, सूखा तथा अन्य मौसमी समस्याएँ कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए सिंचाई, कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, पशुपालन और गैर-कृषि रोजगार के विस्तार की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

शिक्षा की स्थिति

शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। जनजातीय समुदायों में शिक्षा का विस्तार रोजगार, आय, स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक गतिशीलता तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच को प्रभावित करता है।

ऐतिहासिक रूप से आर्थिक कठिनाइयों, विद्यालयों की दूरी, पारिवारिक श्रम की आवश्यकता तथा जागरूकता की कमी के कारण कुछ जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम रहा है। आधुनिक समय में छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उपलब्ध सामग्री में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति तथा आवासीय विद्यालय जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

शिक्षा के विस्तार का प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं पर महत्वपूर्ण हो सकता है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की उपलब्धता से सरकारी एवं निजी रोजगार, कौशल-आधारित कार्य तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

फिर भी केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता, डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति, परिवहन, छात्रावास तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर

सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक स्वास्थ्य की स्थिति है। जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा प्राथमिक चिकित्सा सेवाएँ जीवन-स्तर को प्रभावित करती हैं।

तराई क्षेत्र के ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों तक दूरी तथा परिवहन की सीमित सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित कर सकती है। गरीबी और कम आय के कारण परिवार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित उपयोग करने में भी कठिनाई अनुभव कर सकते हैं।

जीवन-स्तर का मूल्यांकन केवल आय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। आवास की गुणवत्ता, पेयजल, शौचालय, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार सुविधाओं को भी इसमें शामिल करना आवश्यक है। अध्ययन सामग्री में कुछ जनजातीय एवं कमजोर समूहों के संदर्भ में आवास, जल, शौचालय और विद्युत सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

रोजगार एवं श्रम संरचना

रोजगार सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। जनजातीय परिवारों में रोजगार का स्वरूप कृषि, कृषि मजदूरी, पशुपालन, वन-आधारित कार्य, निर्माण कार्य, छोटे व्यापार तथा अन्य असंगठित गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है।

सीमित कृषि भूमि वाले परिवारों के लिए कृषि मजदूरी आय का प्रमुख स्रोत बन सकती है। मौसमी रोजगार की स्थिति में वर्ष के अलग-अलग समय में रोजगार की उपलब्धता बदलती रहती है। इससे आय की स्थिरता प्रभावित होती है और परिवारों को अन्य क्षेत्रों में अस्थायी प्रवास करना पड़ सकता है।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। कंप्यूटर, निर्माण, परिवहन, पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा छोटे व्यवसायों से संबंधित कौशल जनजातीय युवाओं को स्थानीय एवं बाहरी बाजार से जोड़ सकते हैं।

इसलिए रोजगार सृजन की रणनीति में स्थानीय संसाधनों तथा पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार व्यवस्था से जोड़ना महत्वपूर्ण होगा।

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भूमिका

जनजातीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कृषि कार्य, पशुपालन, घरेलू गतिविधियों, वन उत्पादों के संग्रहण, हस्तशिल्प तथा छोटे व्यवसायों में योगदान देती हैं। इसके बावजूद महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यांकन कई बार पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता।

शिक्षा एवं कौशल विकास महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, लघु वित्त, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों के विपणन के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

महिला सशक्तीकरण से परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन-स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः जनजातीय विकास की किसी भी रणनीति में महिलाओं को सक्रिय भागीदार बनाना आवश्यक है।

पारंपरिक संस्कृति एवं सामाजिक परिवर्तन

जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान उनके सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। परंपराएँ, लोककला, भाषा, त्योहार, खान-पान, पहनावा, धार्मिक विश्वास तथा सामुदायिक संस्थाएँ उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में सहायता करती हैं।

आधुनिक शिक्षा, बाजार, संचार, नगरीकरण तथा रोजगार के विस्तार से पारंपरिक जीवनशैली में परिवर्तन हो रहा है। एक ओर आधुनिक सुविधाओं के कारण जीवन-स्तर में सुधार की संभावनाएँ बढ़ी हैं, दूसरी ओर कुछ पारंपरिक व्यवसाय एवं सांस्कृतिक प्रथाएँ कमजोर हो सकती हैं।

इसलिए विकास की प्रक्रिया में आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है। पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प को बाजार से जोड़कर सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक अवसर में बदला जा सकता है।

सरकारी योजनाएँ एवं विकास

स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान तथा विकासात्मक योजनाएँ लागू की गई हैं। शिक्षा, रोजगार, आवास, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

अध्ययन सामग्री में जनजातीय विकास के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन, लघु वनोपज के विकास, छात्रवृत्ति तथा वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं का उल्लेख मिलता है।

इन योजनाओं की सफलता केवल उनके निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि लक्षित समुदायों तक उनकी वास्तविक पहुँच पर भी निर्भर करती है। जागरूकता की कमी, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, दस्तावेजों की समस्या, भौगोलिक दूरी तथा संस्थागत सहायता का अभाव योजनाओं के लाभ को सीमित कर सकते हैं।

अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता, पारदर्शिता, सरल प्रक्रिया और नियमित निगरानी आवश्यक है।

सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं को निम्न रूप में देखा जा सकता है—

1. सीमित भूमि स्वामित्व एवं भूमिहीनता
2. कृषि पर अत्यधिक निर्भरता
3. शिक्षा का अपेक्षाकृत निम्न स्तर
4. रोजगार के सीमित अवसर
5. स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच
6. पूँजी एवं ऋण की समस्या
7. तकनीकी ज्ञान का अभाव
8. बाजार तक सीमित पहुँच
9. प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

10. कौशल प्रशिक्षण की कमी

11. सरकारी योजनाओं की अपर्याप्त जानकारी

12. ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की कमी

इन समस्याओं का समाधान केवल एक क्षेत्र में हस्तक्षेप से संभव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, वित्त, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।

विकास की संभावनाएँ

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। क्षेत्र की उपजाऊ भूमि, कृषि संसाधन, पशुधन, वन संसाधन, पारंपरिक कौशल और स्थानीय संस्कृति आर्थिक विकास का आधार बन सकते हैं।

कृषि विविधीकरण

पारंपरिक कृषि के साथ बागवानी, सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य उच्च-मूल्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

हस्तशिल्प एवं पारंपरिक कौशल

जनजातीय कला, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक उत्पादों को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं ऑनलाइन बाजार से जोड़ने से आय के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

कौशल विकास

युवाओं के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण रोजगार तथा स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकता है।

महिला उद्यमिता

स्वयं सहायता समूहों एवं लघु वित्त के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत किया जा सकता है।

पर्यटन

प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के आधार पर स्थानीय पर्यटन विकसित किया जा सकता है। इससे आवास, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और स्थानीय सेवाओं में रोजगार उत्पन्न हो सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बाजार, डिजिटल शिक्षा और संचार सुविधाओं का विस्तार जनजातीय उद्यमों को व्यापक बाजार से जोड़ सकता है।

निष्कर्ष

भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा उनके प्राकृतिक पर्यावरण, संसाधनों, भूमि व्यवस्था, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों की आजीविका प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि पर आधारित रही है, जबकि आधुनिक समय में शिक्षा, बाजार, तकनीक, सरकारी योजनाओं तथा नए रोजगार अवसरों ने परिवर्तन की नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं।

फिर भी विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ बनी रह सकती हैं। सीमित भूमि, कम आय, कृषि पर निर्भरता, रोजगार की अनिश्चितता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच तथा बाजार और वित्तीय संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ विकास को प्रभावित करती हैं।

इसलिए जनजातीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, कृषि विविधीकरण, महिला सशक्तीकरण, आधारभूत संरचना, वित्तीय समावेशन तथा स्थानीय संसाधन आधारित उद्यमिता को एकीकृत रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है। विकास योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने से योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। साथ ही, जनजातीय संस्कृति एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार समावेशी एवं क्षेत्र-विशिष्ट विकास रणनीति भारत-नेपाल तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में दीर्घकालिक सुधार का आधार बन सकती है।

Author's Declaration & Publication Consent: The author(s) declare that the manuscript is original, accurate to the best of their knowledge, and does not knowingly infringe any copyright, privacy, or other third-party rights. All necessary permissions, ethical approvals, disclosures, and consents, where applicable, have been obtained. The author(s) accept responsibility for the content, data, interpretations, conclusions, authorship, and compliance with applicable research and publication ethics. Any conflicts of interest and funding sources have been appropriately disclosed. The author(s) authorize the Journal and Publisher to publish and disseminate the article under the Creative Commons Attribution Non-commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, भारत की जनगणना: अनुसूचित जनजाति संबंधी जनसंख्या आँकड़े, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधी रिपोर्ट, नई दिल्ली।
4. उत्तर प्रदेश सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग की रिपोर्ट, लखनऊ।
5. भारत सरकार, जिला जनगणना पुस्तिका, जनगणना संचालनालय।
6. भारत सरकार, भारत में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संबंधी सांख्यिकीय प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. नाबार्ड, ग्रामीण विकास एवं आजीविका संबंधी रिपोर्ट, मुंबई।
8. रावत, ए. एवं सिंह, एस. के., जनजातीय समाज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन।
9. प्रसाद, एस. के., भारत में जनजातीय विकास एवं सामाजिक परिवर्तन।
10. संबंधित जिला सांख्यिकी कार्यालय एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रतिवेदन।

Publisher's Note: The statements, opinions, findings, interpretations, and conclusions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Journal, its Editors, Editorial Board, reviewers, or Publisher. Responsibility for the accuracy, integrity, and scholarly content of the article rests primarily with the author(s). The Journal, Editors, and Publisher exercise reasonable editorial and ethical oversight in accordance with the Journal's established policies. However, to the extent permitted by applicable law, they shall not be responsible for any consequences arising from the use, application, or interpretation of the information contained in the article. The Publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.